कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही कि अपना आज अच्छा करो।
– अज्ञात

अपनी ढपली अपना राग

दुर्भाग्य यह कि ट्रंप जैसे ताकतवर लोगों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वे बस तात्कालिकता में जी रहे हैं और अपने निजी हानि–लाभ देख रहे हैं। अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और अपनी जीत के लिए ट्रंप कोयला खदानों वाले इलाकों को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।

रश्मि वर्मा

अमेरिका अब पेरिस जलवायु समझौते से बाकायदा अलग होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र को उसने आधिकारिक तौर पर इस एग्रीमेंट से बाहर आने की सूचना दे दी है। इसके साथ ही समझौते से उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो एक साल लंबी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पेरिस जलवायु समझौता 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। पूर्व अमेरिकी प्रेजिडेंट बराक ओबामा इसके बड़े पैरोकारों में थे, जबकि डॉनल्ड ट्रंप शुरू से ही इसके विरोधी रहे हैं। इस समझौते से हटना उनके चुनावी वादों में एक था।

ट्रंप की दलील है कि पेरिस समझौता एकतरफा है। इसके तहत अमेरिका खरबों डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि रूस, चीन और भारत जैसे प्रदूषण फैलाने वाले देश कुछ नहीं दे रहे हैं। जून 2017 में ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौता न मानने की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया था। कई देशों ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया पर उन्हें निराशा मिली। वहां से आगे बढ़कर औपचारिक रूप से समझौते से अलग होने का फैसला अमेरिका ने ऐसे समय किया है, जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित है। हाल में इस संबंध में आए अध्ययनों का स्पष्ट इशारा है कि जल्द ही कार्बन उत्सर्जन रोकने के गंभीर उपाय नहीं किए गए तो दुनिया के कई हिस्सों को भयावह संकट का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य यह कि ट्रंप जैसे ताकतवर लोगों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वे बस तात्कालिकता में जी रहे हैं और अपने निजी हानि–लाभ देख रहे हैं। अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और अपनी जीत के लिए ट्रंप कोयला खदानों वाले इलाकों को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कुछ साल पहले इनके बंद होने से लोग बेरोजगार होने लगे थे। पिछले चुनाव में ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के बल पर चुने गए और उन इलाकों में बेरोजगारी घटाने की कोशिश की। अभी कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए खदानें बंद करने की नौबत आती तो उन क्षेत्रों में ट्रंप का विरोध हो सकता था।

बहरहाल, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और संसार के दूसरे सर्वाधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश के पेरिस समझौते से हटने के चलते जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने की मुहिम कमजोर पड़ेगी, इस बात का अहसास कई अमेरिकी राजनेताओं को भी है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने समझौते से अलग होने के ट्रंप के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका में पर्यावरण से जुड़े कुछ ट्रस्टों ने भी इस फैसले को गलत बताया है और यहां तक कहा है कि इसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं। ऐसा हो या न हो मगर वैश्विक मंचों पर अमेरिका की भूमिका इससे जरूर प्रभावित होगी। रास्ता एक ही है। वह यह कि बाकी देश इस समझौते पर मजबूती से एकजुट होकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की मुहिम तेज करें और आम अमेरिकियों का मन बदलने का इंतजार करें।

समय को प्रकाशित

ओशो

ओशो लिखते हैं कि– सामान्य रूप से आपदायें आपको संसार के प्रति जागरूक करती हैं और आपके दृष्टिकोण को व्यापक करती हैं। ओशो ने कहा है कि– ष्आपदा का समय आपको, वास्तविकता के प्रति जागरूक करता है।ष यह हमेशा भंगुर होता है और इस समय सभी खतरे में होते हैं। जैसे कि– "साधारण समय में आप जब गहरी नींद में होते हैं, तो आप इसे नहीं देखते है, क्योंकि आप सपनों में भविष्य के दिनों के लिए सुंदर चीजों की कल्पना में खोए हुए होते हैं।"जब खतरा निकट होता है, तब अचानक से आपको ज्ञात होता है कि– "शायद वहाँ कोई भविष्य, कोई आने वाला कल नहीं हो सकता है, केवल यही पल हैं, जो आपके पास हैं।" इसलिए आपदा का समय बहुत ही प्रत्यक्ष होता है। वे इस संसार में कोई भी नई चीज नहीं लाते हैं। ये आपको संसार के सामान्य रूप से आपको अवगत और जागृत करते हैं।

संपादकीय

बौखलाहट का राजनय

जम्मू–कश्मीर को लेकर भारत के हालिया संविधान संशोधन से पाकिस्तान के हुक्मरानों में बौखलाहट है। राज्य के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत के फैसले के जवाब में पाकिस्तान की सरकार ने कई इकतरफा घोषणाएं की हैं। उसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध को निलंबित कर दिया है और राजनयिक संबंधों का स्तर घटा दिया है। अपने हवाई क्षेत्र के कुल नौ में से तीन कॉरिडोर भी उसने भारतीय नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिए हैं। जम्मू–कश्मीर मसले को वह एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि इस फैसले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। भारत अपने एक राज्य के प्रशासन को लेकर क्या फैसला करता है, यह उसका आंतरिक मामला है। इस पर पाकिस्तान की इतनी तीखी प्रतिक्रिया समझ से परे है। पाक अधिकृत कश्मीर में वह किस तरह से शासन चला रहा है, इस पर भारत कहां कुछ कहता है? जब–तब वहां जारी आतंकी गतिविधियों की निंदा जरूर की जाती है, जो खुद पाकिस्तान के लिए भी कुछ कम सिरदर्दी नहीं है। अभी जो कदम पाकिस्तान ने खीझ में उठाए हैं, वे उसके लिए भी घातक हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को निलंबित करने का ज्यादा नुकसान उसी का होगा। कारण यह कि पाकिस्तान कई जरूरी चीजों का आयात भारत से करता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद व्यापार संबंधों में तनाव के चलते भारत से पाकिस्तान को होने वाले निर्यात में पहले ही कमी आई हुई है। इस मामले में भारत उस पर ज्यादा निर्भर नहीं है। इसी तरह हवाई क्षेत्र के कुछ कॉरिडोर को बंद करने से उड़ानों को 12 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा।

आईपीसीसी की रिपोर्ट का साफ इशारा यह है कि हमें अपनी जीवन-पद्धति बदलनी होगी। यह तभी संभव है जब हम यह मानने को तैयार हों कि जिसे हम विकास समझ रहे हैं वह एक मायने में विनाश है।

यह कैसा विकास

नवीन शाह

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर–सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने बृहस्पतिवार को जलवायु परिवर्तन और भूमि संबंधी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया को घेर रही इस स्थायी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जीवाश्म–ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकना ही काफी नहीं है। इसके लिए खेती में बदलाव करने होंगे, शाकाहार को बढ़ावा देना होगा और जमीन का इस्तेमाल सोच–समझकर करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 23 फीसदी कृषियोग्य भूमि का क्षरण हो चुका है, जबकि भारत में यह हादसा 30 फीसदी भूमि के साथ हुआ है। जमीनों का रेगिस्तानीकरण जारी है। तकनीकी तौर पर मरुस्थल उस इलाके को कहते हैं, जहां पेड़ नहीं सिर्फ झाड़ियां उगती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पैदावार में गिरावट आ रही है और खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। इससे खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी।

अनुमान है कि 2050 तक खाद्य वस्तुओं की कीमतें 23 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। 25–30 प्रतिशत खाद्य पदार्थ अभी यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। इस बर्बादी को कम करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और खाद्य सुरक्षा में सुधार

होगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट का साफ इशारा यह है कि हमें अपनी जीवन–पद्धति बदलनी होगी। यह तभी संभव है जब हम यह मानने को तैयार हों कि जिसे हम विकास समझ रहे हैं वह एक मायने में विनाश है। हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां से एकाएक पीछे लौटना मुमकिन नहीं, पर विकास की दिशा बदली जा सकती है, उसकी रफ्तार घटाई जा सकती है। आईपीसीसी रिपोर्ट जो कह रही है, पहले वही बात दूसरी रिपोर्टों ने भी कही है। भूमि की बर्बादी को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक रिपोर्ट में भी भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30 फीसदी हिस्सा मरुस्थल बन जाने की बात दो साल पहले आ चुकी है। प्राकृतिक कारणों या मानवीय गतिविधियों के चलते जैविक उत्पादकता में कमी की स्थिति को भू–क्षरण कहा जाता है।

जिन इलाकों में यह भू–जल के खात्मे के चलते हो रहा है, वहां इसे मरुस्थलीकरण का नाम दिया गया है। लेकिन शहरों का दायरा बढ़ने के साथ सड़क, पुल, कारखानों और रेलवे लाइनों के निर्माण से खेतिहर जमीन का खात्मा और बची जमीन की उर्वरा शक्ति कम होना भू–क्षरण का दूसरा रूप है, जिस पर अभी बात ही नहीं होती। वन क्षेत्र का लगातार खत्म होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अभी आईपीसीसी रिपोर्ट में आए सुझावों पर अमल शुरू किया जा सके तो थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके मुताबिक बिना जुताई वाली खेती और खाद के सीमित, लक्षित उपयोग से 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 18 फीसदी की कमी की जा सकती है और अगर हम खानपान में साग–सब्जियां बढ़ाएं और रेड मीट का इस्तेमाल घटा दें तो उत्सर्जन में एक तिहाई कमी मुमकिन है।

सूडोकु नवताल- 5162

मध्यम

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5161 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	6	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

युवा महिला गणितज्ञों के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

चंद्रभूषण। ईरान की जीनियस गणितज्ञ मरियम मिर्जाखानी की याद में युवा महिला गणितज्ञों के लिए 50 हजार डॉलर का एक पुरस्कार शुरू किया गया है। अमेरिका में दिया जाने वाला यह पुरस्कार संसार में कहीं की भी महिला गणितज्ञ को उसकी डॉक्ट्रेट थीसिस स्वीकृत होने के दो साल के अंदर ही दिया जा सकता है। इस समय सीमा के बाद पुरस्कार की अर्हता समाप्त हो जाएगी। गणित की अमूर्त दुनिया में लैंगिक विभाजन और इससे जुड़े पूर्वाग्रहों के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन समाज में अगर ऐसे पूर्वाग्रह मौजूद हों तो उनसे निपटना भी गणितज्ञों का ही काम है। लड़कियों का गणित कमजोर होता है, ऐसी एक धारणा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चली आ रही है, हालांकि हकीकत इससे अलग है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से लेकर प्योर मैथमेटिक्स तक गणित के सारे क्षेत्रों में लड़कियों–लड़कों के बीच अब कोई फर्क नहीं बचा है। चार साल के अंतर पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियंस को ही मिलता है।